Hindustan Times

Open pit in Meerut: NHRC issues notices to chief secretary, DGP; seeks probe report on death of 3 children

https://www.hindustantimes.com/cities/others/open-pit-in-meerut-nhrc-issues-notices-to-chief-secretary-dgp-seeks-probe-report-on-death-of-3-children-101754747163064.html

By HT Correspondent, Lucknow/meerut

Updated on: Aug 09, 2025 07:16 pm IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has requested a report from the Uttar Pradesh director general of police (DGP) and state's chief secretary regarding the death of three children who fell into an open pit in Meerut district

The National Human Rights Commission (NHRC) has requested a report from the Uttar Pradesh director general of police (DGP) and state's chief secretary regarding the death of three children who fell into an open pit in Meerut district.

The incident occurred on August 3, in Sival Khas area of Meerut district, where three children drowned after falling into a pit that had been dug approximately 40 days earlier, left unsecured, and had filled with rainwater. (FOR REPRESENTATION)

Taking suo motu cognizance of media reports, the NHRC has issued notices to the CS and DGP of Uttar Pradesh over the deaths of three children, aged 8-9, who drowned on August 3 in a six-foot-deep pit allegedly left open by a builder during construction in a newly developed colony in Meerut district. The Commission, on August 8, sought a detailed report within two weeks.

The notice stated that the report from Uttar Pradesh should detail the status of the investigation and specify whether any compensation has been provided to the victims' next of kin.

The incident occurred on August 3, in Sival Khas area of Meerut district, where three children drowned after falling into a pit that had been dug approximately 40 days earlier, left unsecured, and had filled with rainwater. According to reports, the children were returning from a shop after buying chocolate when they accidentally fell in, resulting in their tragic deaths.

The NHRC noted that, if accurate, the details in the news report raise a serious issue of violation of the human rights of the victim children. Therefore, it has issued notices to the CS and the DGP, seeking a detailed report within two weeks.

Times of India

NHRC notice to UP govt, DGP over death of 3 kids in pit dug by builder

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bareilly/nhrc-notice-to-up-govt-dgp-over-death-of-3-kids-in-pit-dug-by-builder/articleshow/123201658.cms

TNN | Aug 9, 2025, 12.04 PM IST

BAREILLY: National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of the death of three children, who drowned in a six-foot-deep water-filled pit dug by a builder in Meerut's Siwal Khas area on Aug 3. It has issued notices to Uttar Pradesh chief secretary and DGP, seeking a detailed report within two weeks. NHRC has also asked for the status of the investigation and whether any compensation has been provided to the children's families. The NHRC, through a statement issued via the Press Information Bureau, said that the contents of the media report, if true, raise serious concerns of human rights violations.

The pit, allegedly dug by a builder and left uncovered, turned into a hazard during the monsoon, becoming a death trap for the children — Manvi, 7, her cousin Shivansh Singh, 8, and Hritik Kumar, 8.

The children allegedly fell into the pit while returning from a nearby shop. Their bodies were recovered from a vacant plot barely 150 m from their homes. Locals said the builder had left the pit open for over a month. An FIR was later filed against him for negligence.

The case took a turn after the postmortem report confirmed drowning but revealed a fractured hyoid bone in Manvi's neck. Her family, along with those of the other victims, have alleged foul play. "Our children never went to that area. It's hard to believe all three drowned without a scream. There are houses nearby. And how does a drowning cause a broken throat?" asked Hritik's father, Himmat Singh.

Police said a separate FIR under BNS section 137(2) was filed by the families, fearing abduction and murder. SP (rural) Rakesh Mishra said, "There were no signs of sexual assault. While the primary cause of death appears to be drowning, the broken hyoid bone is suspicious. We're investigating all angles."

Doctors are also sceptical. "In children, the hyoid bone is soft cartilage. It rarely fractures unless there's strangulation or blunt trauma to the throat," said senior ENT surgeon Dr Ankur Gupta.

The incident gained widespread attention after CM Yogi Adityanath sought a report from senior officials. The children's families and villagers have demanded swift police action and proper compensation.

Amar Ujala

UP News: मेरठ में पानी भरे गड्ढे में गिरने से तीन बच्चों की मौत का मामला, NHRC ने तलब की रिपोर्ट

https://www.amarujala.com/lucknow/case-of-death-of-three-children-due-to-falling-in-water-filled-pit-in-meerut-nhrc-summoned-report-2025-08-09?src=top-subnav-amp

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sun, 10 Aug 2025 12:09 AM IST

सार

लखनऊ

मेरठ में पानी भरे गड्ढे में गिरने से तीन बच्चों की मौत के मामले में NHRC ने रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने जांच की स्थिति और पीड़ित परिजनों को दिए गए मुआवजे का विवरण देने को कहा है।

विस्तार

यूपी के मेरठ में गड्ढे में गिरने से तीन बच्चों की मौत की घटना का संज्ञान लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने दो हफ़्ते में जांच की स्थिति और पीड़ित परिजनों को दिए गए मुआवजे का विवरण देने को कहा है।

बताते चलें कि तीन अगस्त को मेरठ में एक नवविकसित कॉलोनी में इमारत के निर्माण के दौरान एक बिल्डर द्वारा बनाया गया छह फीट गहरा गड्ढा ऐसे ही छोड़ दिया गया था।

इस गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 8-9 साल के तीन बच्चों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि वे चॉकलेट खरीदकर एक दुकान से लौट रहे थे। इसी समय गड्ढे में गिर गए थे। मामले में एनएचआरसी ने रिपोर्ट तलब की है।

Jagran

तीन बच्चों की मौत के मामले में NHRC ने मांगा जवाब, दूसरी तरफ मेरठ पुलिस की लचर कार्रवाई, आरोपित बिल्डर को मिली जमानत

Meerut News मेरठ के सिवालखास में अनम गार्डन कॉलोनी में तीन बच्चों की मौत के मामले में ग्रामीणों ने बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। उधर आरोपित बिल्डर को जमानती धाराओं में गिरफ्तार किया गया। उसे कोर्ट ने रिहा कर दिया है।

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-meerut-news-villagers-angered-after-three-children-die-in-siwalkhas-national-human-rights-commission-seeks-report-24008179.html

By sushil kumar Edited By: Praveen Vashishtha Updated: Sat, 09 Aug 2025 03:04 PM (IST)

पुलिस की लचर कार्रवाई से तीन बच्चों की मौत पर बिल्डर को मिली जमानत

HighLights

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से दो सप्ताह में जवाब मांगा

शीर्ष अफसरों के नेतृत्व करने पर भी तीनों की मौत की गुत्थी पुलिस सुलझा नहीं सकी

जागरण संवाददाता, मेरठ। सिवालखास की निर्माणाधीन अनम गार्डन कालोनी फेस-तीन में तीन बच्चों की मौत के मामले में बिल्डर असलम पर ढीली कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। उनका आरोप है कि गंभीर मामले में असलम को बचाने की कवायद की गई है। जमानती धाराओं में कार्रवाई होने पर असलम को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। उधर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तीन बच्चों की मौत को गंभीर मामला मानते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी से दो सप्ताह में पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है।

आयोग ने पूछा है कि कालोनी में बिल्डर ने गड्ढा खोदकर छोड़ दिया, क्या उसकी वजह से बच्चों की मौत हुई है? सिवालखास के वार्ड नंबर एक निवासी हिम्मत सिंह के आठ वर्षीय बेटे ऋतिक और पड़ोसी जितेंद्र की नौ वर्षीय बेटी मानवी उसके भाई मोनू का आठ वर्षीय बेटा शिवांस उर्फ शिबू रविवार सुबह 10 बजे घर से चाकलेट लेने गए थे। उसके बाद तीनों बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाया। बच्चों को ढूंढने के लिए कस्बे में अभियान चलाया गया। करीब 20 घंटे बाद सोमवार सुबह छह बजे तीनों बच्चों के शव कस्बे के बाहरी छोर स्थित अनम गार्डन कालोनी के पानी भरे गड्ढे में मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मानवी की गला दबाकर हत्या की बात आई, जबकि ऋतिक और शिवांश की पानी में डूबने से मौत होना आया।

पुलिस ने अज्ञात में दर्ज किया हत्या का मुकदमा

पुलिस ने अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज किया। अभी तक पुलिस को कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिल पाया हैं, जिससे पुलिस उक्त घटना को हत्या की तरफ ले जाए। इसी के चलते पुलिस ने दूसरा मुकदमा कालोनी काट रहे बिल्डर असलम निवासी मुरादनगर जिला गाजियाबाद के खिलाफ दर्ज किया। आरोप लगाया कि कालोनी से मिट्टी चोरी करने की वजह से गड्ढा होने पर हादसा हुआ।

पुलिस ने जमानती धाराओं में बिल्डर को किया गिरफ्तार

पुलिस ने जमानती धाराओं में बिल्डर असलम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

दैनिक जागरण की खबर का आयोग ने लिया संज्ञान

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उप निदेशक जैमिनी कुमार श्रीवास्तव ने तीन बच्चों की मौत पर दैनिक जागरण की खबर पर संज्ञान लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी से पूरे घटनाक्रम पर रिपोर्ट मांगी है। एएसपी देहात डा. राकेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस की टीमें तीनों बच्चों की मौत पर काम कर रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट के साथ मौके से वीडियो व फोटो लैब भेजे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला हैं, जिससे तीनों बच्चों की मौत के मुकदमे को हत्या की तरफ ले जाया जा सके।

Punjab Kesari

खाना मांगने पर रसोईया ने छात्रा को गर्म करछी से जलाया, एनएचआरसी ने जहानाबाद के DM-SP को भेजा नोटिस

https://bihar.punjabkesari.in/bihar/news/nhrc-sent-notice-to-dm-sp-of-jehanabad-in-case-of-burning-a-girl-student-with-a-2194242

Edited By Swati Sharma, Updated: 09 Aug, 2025 02:33 PM

Bihar News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार के जहानाबाद में आवासीय विद्यालय के रसोइये से खाना मांगने पर कथित तौर पर गर्म करछी से एक छात्रा को जलाने के मामले में जिले के अधिकारियों को नोटिस जारी किये हैं। एक बयान में कहा गया है कि यह घटना...

Bihar News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार के जहानाबाद में आवासीय विद्यालय के रसोइये से खाना मांगने पर कथित तौर पर गर्म करछी से एक छात्रा को जलाने के मामले में जिले के अधिकारियों को नोटिस जारी किये हैं। एक बयान में कहा गया है कि यह घटना शकूराबाद क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में हुई।

बयान के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने "मीडिया में आई एक खबर का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि अपने आवासीय विद्यालय के रसोइये से खाना मांगने पर छात्रा के शरीर पर गर्म करछी लगा दी गई, जिसके कारण वह जल गई।" बयान में कहा गया है कि आयोग का मानना है कि यदि खबर सत्य है, तो इससे पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। बयान में कहा गया है कि इसलिए, जिला मजिस्ट्रेट और जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

बयान में कहा गया है कि रिपोर्ट में छात्रा की स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी जाए। पांच अगस्त को प्रकाशित खबर के अनुसार, रसोइया पर पहले भी इसी तरह की हरकत का आरोप लगा था और शिकायत मिलने के बाद उसे दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था।

Amar Ujala

तीन मासूमों की मौत का मामला : नोटिस के बाद हरकत में आए अफसर, जांच तेज

https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/meerut/case-of-death-of-three-innocent-people-officers-came-into-action-after-notice-investigation-intensified-meerut-news-c-14-1-mrt1027-942871-2025-08-10

मेरठ ब्यूरो | Updated Sun, 10 Aug 2025 01:49 AM IST

मेरठ। सिवालखास में एक गड्ढे में गिरकर तीन बच्चों के मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के नोटिस के बाद अफसर हरकत में आ गए हैं। इस प्रकरण की जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अफसरों को दो सप्ताह के अंदर ही मामले की विस्तृत रिपोर्ट देनी है।दरअसल, आयोग ने शुक्रवार को घटना से जुड़ीं खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी को नोटिस जारी किया था। बता दें कि तीन अगस्त को जिले में सिवालखास में काटी जा रही नई कॉलोनी में प्लाट काटने के दौरान बिल्डर द्वारा छोड़े गए छह फीट गहरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों शिवांश (8), ऋतिक (8) और मानवी (7) की मौत हो गई थी। बच्चे चॉकलेट खरीदकर दुकान से लौटते समय लापता हुए और अगले दिन तीनों के शव गड्ढे से मिले। पुलिस का भी कहना है कि डूबने से मौत हुई।एनएचआरसी ने कहा, रिपोर्ट में मामले की जांच की स्थिति और पीड़ितों के परिजनों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) की जानकारी शामिल होनी चाहिए।

इस मामले में ही शुक्रवार को जानी थाना पुलिस ने बिल्डर असलम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। ग्रामीणों में चर्चा है कि जब एक साथ तीन बच्चों की मौत हुई है तो दो बच्चों की मौत में ही बिल्डर को जेल क्यों भेजा गया है। क्या तीन बच्चें की हत्या का मामला अलग-अलग है।

Hindustan

तीन बच्चों की मौत मामले में बिल्डर को जमानत, पुलिस की जांच तेज

Meerut News - मेरठ/जानी में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए तीन बच्चों के शव अमन गार्डन कॉलोनी में मिले। बिल्डर हाजी असलम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जमानत मिल गई। एनएचआरसी ने मामले का संज्ञान...

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/meerut/story-three-missing-children-found-dead-in-meerut-builder-arrested-amid-nhrc-inquiry-201754775669082.html

10 अगस्त 2025

मेरठ/जानी। सिवालखास में छह दिन पूर्व घर से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए तीन बच्चों के शव घर के पास कट रही अमन गार्डन कॉलोनी में पानी से भरे गहरे गड्ढे में मिले थे। बिल्डर के खिलाफ लापरवाही व गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से शुक्रवार देर शाम जमानत मिल गई। उधर, पुलिस ने नये सिरे से जांच तेज कर दी है। रविवार को कस्बा सिवालखास में नौ वर्षीय मानवी पुत्री जितेंद्र, आठ वर्षीय ऋतिक पुत्र हिम्मत व आठ वर्ष के सिब्बू पुत्र मोनू बाल्मिकी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए थे।

सोमवार सुबह तीनों बच्चों के शव पास ही में एक निर्माणाधीन अमन गार्डन कालोनी फेस तीन में पानी से भरे गहरे गड्ढे में मिले थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना का निरीक्षण करने आए एडीजी मनु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी,एसएसपी विपिन टाडा आदि अधिकारियों ने कालोनाईजर हाजी असलम निवासी मुरादनगर की लापरवाही व गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया था। पुलिस ने बिल्डर हाजी असलम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से बिल्डर को जमानत मिल गई।

एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, पुलिस-प्रशासन में हड़कंप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की ओर से तीन बच्चों की मौत के मामले में मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेने के बाद पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मचा है। एनएचआरसी ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब शासन की ओर से डीएम, एसएसपी से जानकारी मांगी गई है। अधिकारी नियमों का भी अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसे मामले में किस तरह मुआवजा दिया जा सकता है। इस पर भी एनएचआरसी ने जवाब मांगा है। डीएम ने कहा कि जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

The Indian Express

Set in place a policy on rehab & compensation for Silicosis-affected workers: Gujarat HC to state

In its 2016 order, the SC had issued directions to pay a compensation of Rs 1 lakh to the kin of deceased from Silicosis

https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/set-in-place-a-policy-on-rehab-compensation-for-silicosis-affected-workers-gujarat-hc-to-state-10180140/lite/

Written by Aditi Raja | Vadodara | Updated: August 10, 2025 02:10 IST

5 min read

The Gujarat High Court recently directed the Principal Secretary of the Department of Labour and Employment of Gujarat to take effective steps to bring about “suitable amendments” to a Government Resolution of March 2024, to set in place a policy for the rehabilitation of Silicosis-affected workers.

The court also directed the state to provide adequate compensation to the kin of the deceased, due to Silicosis, in line with the 2016 and 2017 orders of the Supreme Court in a 2006 Writ Petition.

A Division bench, of Chief Justice Sunita Agarwal and Justice DN Ray, was hearing a petition filed by the People’s Training and Research Centre (PTRC) as well as the next of kin of 19 deceased persons, seeking compliance of a March 11, 2024 Gujarat government resolution to “enhance the financial assistance” in compliance of the Supreme Court decision dated April 11, 2017.

The Gujarat HC while issuing the oral order considered the submissions made by the petitioner and the respondents in the case and an order of the Supreme Court of August 6, 2024, which directs the Chief Secretaries of state, including Gujarat, to “ensure that adequate compensation is received by the affected workers or their next of kins as swiftly as possible”.

The Gujarat HC, in its August 1 oral order, said “… We find that effective steps have not been taken at the ends of the concerned department of the State… It is evident that there is a substantial delay on the part of the officers of the State in effective implementation of the directions (of 2016 and 2017) of the Apex Court, which has resulted in granting lesser benefits to the applicants, who had submitted applications after (the SC orders). Moreover, the timeline of 90 days for moving such an application is practically not feasible and it seems that there has been no application of mind to the recommendation for increasing the timeline looking at the sensitivity of the matter and the social fabric of the society. The Government resolution dated March 11, 2024 does not provide for rehabilitation of the victims, which has resulted in rejection of the applications of some of the beneficiaries petitioners herein.”

The court order said, “We, therefore, direct the Principal Secretary, Department of Labour and Employment to look into the matter and take effective steps for bringing suitable modifications / amendments / substitution of the Government

resolution dated March 11, 2024 so as to set in place the policy for rehabilitation of the affected workers with the disease ‘Silicosis’ and to provide adequate compensations to the kin of the deceased died due to ‘Silicosis’, in the true letter and spirit of the decision of the Apex Court.”

Directing the Principal Secretary of the Department of Labour and Employment to file an affidavit in compliance with the directions on the next date of hearing on August 29, the Gujarat HC said that claims of the 19 beneficiary-petitioners “shall be given fresh consideration in light of the decision of the Apex Court for providing adequate compensation and the claims of those, which have been rejected on the ground of delay, shall be considered afresh on merits.”

The court further said that the Chief Labour Commissioner of Gujarat is “required to take appropriate steps” for the consideration of claim of the beneficiaries and a policy in strict compliance of the orders of the Supreme Court “shall be set in place by issuance of a fresh Government resolution, wherein effective date is also to be suitably indicated.”

In its 2016 order, the SC had issued directions to pay a compensation of Rs 1 lakh to the kin of deceased from Silicosis as well as deposit an amount of Rs 2 lakh in each of their names in fixed deposit to allow the next of kin to avail the monthly interest accruing from the deposit, based on a recommendation of the National Human Rights Commission (NHRC).

The NHRC had conducted a survey regarding the problem of ‘Silicosis’ affecting people working in stone mines and other silicon dust producing plants as per the SC direction. The SC had directed the Chief Secretaries of each state to make all arrangements facilitating the survey and preparation of reports in cases of Silicosis as well as “for detection of such disease amongst the workers of the weaker sections and issuance of appropriate guidelines in the matter of prevention and treatment of ‘Silicosis’ and other occupational disease, including for compensation, medical treatment and other rehabilitation measures,” the Gujarat High court order states. It was noted by the Supreme Court in the said 2016 order that severity of the problems is prevalent mainly in the states of Delhi, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Jharkhand and Puducherry. The SC had issued further directions in an order in April 2017. The petitioners had contended that though the Gujarat government had framed the policy for providing compensation with the last resolution dated March 3, 2024, the prevailing policy was “not in compliance with the directions” of the SC order.

The HC order also noted that the petitioners had pointed out that “no policy for rehabilitation of persons affected with the disease ‘Silicosis’ was framed in the State of Gujarat”, as per the recommendations of the NHRC, “which is also clear from the admission in the affidavit filed” on behalf of one of the respondents, the Chief Labour Commissioner of Gujarat, the HC noted. Therefore, “lesser benefits were provided to the beneficiaries” as against the decision of the Supreme Court.

Menafn

Sidharthan’s Death: Kerala HC Lets Parents Of Ragging Victim Withdraw Rs 7 Lakh NHRC Compensation

https://menafn.com/1109906537/Sidharthans-Death-Kerala-HC-Lets-Parents-Of-Ragging-Victim-Withdraw-Rs-7-Lakh-NHRC-Compensation

Date 2025-08-09 08:14:05 (MENAFN- AsiaNet News)

Kochi: The Kerala High Court on Friday, August 8 permitted the parents of deceased veterinary student Sidharthan JS, who allegedly died by suicide last year due to ragging, to withdraw ₹7 lakh deposited by the state government in the court's registry as per its earlier order. The interim relief came from a Division Bench comprising Chief Justice Nitin Jamdar and Justice Basant Balaji, which is hearing the state's challenge to a National Human Rights Commission (NHRC) compensation award. The NHRC had ordered the payment on October 1, 2024, to Sidharthan legal heirs. While admitting the writ petition filed by the state government against the award, the Bench allowed the withdrawal on the condition that Sidharthan's parents file an undertaking that the amount would be subject to the outcome of the case.

Appearing for the parents, the counsel told the court that the family faced severe financial difficulties but stressed that no monetary sum could ever compensate for their loss. The court clarified that the permission to withdraw would not affect any other legal remedies available to them. The counsel also expressed an“emotional dilemma” in taking the money and suggested depositing it in a nationalised bank instead. The Bench left the decision to the parents, granting them liberty to take any steps they deemed appropriate. The case will be heard next on September 8.

What happened to Sidharthan?

On February 18, 2024, Sidharthan, a native of Thiruvananthapuram, was found dead in the restroom of his hostel at Pookode Veterinary College. While the police were quick to classify it as a suicide, the case was shrouded in mystery. Suspicion arose due to the injuries found on Sidharthan's body and the unusual behavior of the college authorities. These factors led his family to demand a thorough investigation into his death. A crucial turning point came when his body was being transported home after a public viewing at the college. A piece of paper thrown into the ambulance revealed shocking details, informing the family that Siddharth had been a victim of severe ragging.

From February 16 onwards, Siddharth was brutally assaulted by SFI activists and others, both on the rocky grounds outside and inside his room. He was stripped down to his undergarments and subjected to a public trial. He was beaten with belts and mobile phone chargers, repeatedly kicked, and left with severe injuries. Shortly after, his body was found in the hostel restroom. The hostel warden and the dean allegedly worked to shield the accused, while the government was also accused of protecting the SFI-affiliated perpetrators. Only after mounting public pressure did the case see any real action.

A high-level investigation was ordered in the case, leading to the arrest of 19 students responsible for Sidharthan's death. Following the Governor's intervention, action was taken against the Vice-Chancellor, Dean, and Warden. A controversy arose when CPM leader and former MLA CK Saseendran allegedly facilitated the accused's appearance at the magistrate's residence, raising questions about the party's stance. Though the case was later handed over to the CBI at the family's request, delays in transferring documents seemingly attempted to slow down the investigation. The High Court had permitted the accused to continue their studies at the Mannuthy campus. However, Sidharthan's family approached the division bench, securing a stay on the order.

Live Law

Veterinary Student Death: Kerala High Court Permits Family To Withdraw ₹7 Lakh Awarded

https://www.livelaw.in/high-court/kerala-high-court/kerala-high-court-veterinary-student-death-family-compensation-300414

By NHRC K. Salma Jennath 9 Aug 2025 4:03 PM (4 mins read)

The Kerala High Court on Friday (August 8) passed an interim order permitting the parents of deceased veterinary student Sidharthan J.S., who allegedly committed suicide last year, to withdraw the amount of Rupees 7 Lakh deposited by the state government with the Registry as per the high court's earlier direction. After admitting the petition, the Division Bench of Chief Justice Nitin Jamdar and Justice Basant Balaji observed:

"...Petition is admitted. In the meanwhile, we permit respondent no 3 and 4 to withdraw the amount deposited on an undertaking being filed in this court that the withdrawal will be subject to the outcome of this petition." The amount was awarded by the National Human Rights Commission to the legal heirs of Sidharthan in its order dated 01.10.2024. The present writ petition was filed by the state government challenging the said award. Earlier, Sidharthan's parents were suo-motu impleaded by the Court as respondents 3 and 4.

When the matter came up, the counsel representing Sidharthan's parents submitted to the Court that an affidavit has been filed by them. It was stated that though the family is going through financial difficulty, the portrayal that a monetary award would compensate for the loss of their son is unbearable. The counsel further submitted that no amount would compensate for the loss suffered by the parents and that deceased's mother had come before the Court several times to seek justice.

Upon hearing the same, the Court added, "The learned counsel for respondents 3 and 4 states that the other remedies, if open, to respondents 3 and 4 in law be not foreclosed because of the permission to withdraw. It is needless to issue this clarification because in this matter we are only considering the challenge to the order passed by the NHRC. In that context, we have permitted respondents 3 and 4 to withdraw the amount." The counsel, thereafter, submitted that there is an emotional dilemma in withdrawing the amount and prayed that the Court may direct the Registry to deposit the amount in any nationalised bank instead. Thereupon, the Court orally stated that it has left it open to them and granted them liberty to take whatever steps are needed. The case is posted on September 8 for hearing.

Background

Sidharthan was a second-year Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry student at the College of Veterinary and Animal Sciences, Pookode in Wayanad who

allegedly committed suicide on February 18, 2024. It was alleged that this was because of ragging and brutal assault by some of his classmates and seniors.

In December 2024, a single bench had quashed the order expelling the accused students and allowed them to take re-admission at the Mannuthy campus. The single bench also directed fresh disciplinary enquiry against the accused.

Aggrieved by the order of the single judge, Sidharthan's mother had filed a writ appeal before the division bench. Since she was not a party in the writ petition, she sought leave to file a third-party appeal and was granted leave to appeal. In May, the appeal was disposed of recording the report of the college, which had expelled all the 19 students and debarred them for three years. The anti-ragging committee had also found them to be indulging in and abetting in ragging.

Case Title: State of Kerala v. Sandeep Vaachaspati and Ors. Case No: WP(C) No. 23660/2025

Times of India

Tribals in Anakapalli district protest demanding roads

https://timesofindia.indiatimes.com/city/vijayawada/tribals-in-anakapalli-district-protest-demanding-roads/articleshow/123207808.cms

TNN | Aug 9, 2025, 10.06 PM IST

Visakhapatnam: Tribals from Jeelugulova and Sompuram Bandha villages in Madugula mandal of Anakapalli district organised a symbolic donkey yatra on Saturday to mark World Indigenous Peoples Day and highlight their ongoing struggle for basic road infrastructure.

According to the protestors, despite living in officially recognised settlements and having been granted housing and utility access, they remain cut off from essential transport facilities. "Our donkey protest was meant to highlight the gap between govt promises and ground realities. Without proper roads, emergencies such as medical treatment and childbirth turn into life-threatening ordeals," they said.

"Over four years have passed since two-room houses were sanctioned for 23 tribal families on Saamalamma Hill, yet the promised land pattas have not been issued. Bureaucratic apathy, frequent transfer of officials, and unfulfilled assurances have only compounded our problems. Although the National Human Rights Commission (NHRC) intervened and claimed progress, conditions on the ground remain bleak. Further, tribal lands are being encroached upon by non-tribal entities, often with official complicity. This failure to protect tribal rights, while simultaneously celebrating Indigenous Peoples Day, exposes a deep hypocrisy. Our protest is not just a demand for roads, but for our dignity, recognition, and justice. Immediate field inspections and administrative accountability are urgently needed," they added.

CPM leader K. Govinda Rao, tribal leader E Narasimhulu, and others participated in the protest.

Janta Se Rishta

NHRC ने कपूरथला के अस्पताल और आधुनिक जेल में उल्लंघन पाया

https://jantaserishta.com/local/punjab/nhrc-finds-violations-in-kapurthala-hospital-and-modern-jail-4201663

Payal 9 Aug 2025 3:30 PM

Jalandhar.जालंधर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष निरीक्षक बाल कृष्ण गोयल ने आज कहा कि आयोग को सिविल अस्पताल और मॉडर्न जेल की जाँच के दौरान कई अनियमितताएँ और उल्लंघन मिले हैं। कपूरथला के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान, आयोग के विशेष निरीक्षक ने आज अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की, अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कर्मचारियों और उपकरणों की कमी पाई और कपूरथला में मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हो रही अत्यधिक देरी का भी संज्ञान लिया। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि वह करोड़ों रुपये की

केंद्रीय निधि जारी होने के बावजूद मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हो रही अत्यधिक देरी के बारे में आयोग के संज्ञान में लाएँगे। गोयल ने कहा कि उन्होंने अस्पताल की विस्तृत रिपोर्ट माँगी है और आयोग की टीम आँकड़ों का विश्लेषण करके अपनी गोपनीय रिपोर्ट अपने अध्यक्ष को सौंपेगी। पंजाब के छह दिवसीय दौरे पर आए विशेष निरीक्षक ने पठानकोट, संगरूर और कपूरथला का दौरा किया है। जिला प्रशासनिक परिसर में एक बैठक के दौरान, जिला अधिकारियों को संबोधित करते हुए, गोयल ने अधिकारियों से जिले भर में मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने में एक ज़िम्मेदार भूमिका निभाने का आग्रह किया। डीसी अमित कुमार पांचाल और एसएसपी गौरव तूरा ने भी बैठक को संबोधित किया और आयोग को जिले में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाने का आश्वासन दिया।